>

Title: Situation arising out of reduction in the food-grains quota for APL families in Chhattisgarh State.

श्रीमती करूणा शुक्ला (जांजगीर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर दिलाना चाहती हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश नवोदय राज्य है, पिछड़ा राज्य, गरीब राज्य है, आदिवासी बाहुल्य राज्य है। लेकिन खेद का विषय है कि केन्द्र सरकार ने हमारे राज्य का एपीएल चावल का कोटा जो कि 60 हजार मिट्रीक टन का होता था, इस साल सिर्फ 740 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इससे राज्य शासन पर 150 करोड़ का अतिरिक्त भार आ गया है। यह विषय मैं इसलिए उठा रही हूं क्योंकि बीच-बीच में केन्द्र की सरकार हमारा कभी शक्कर का कोटा कम कर देती है, कभी मिट्टी के तेल का कोटा कम करती है। इसके अलावा 398 मेगावाट बिजली केन्द्र पूल से हमेशा के लिए देना बंद कर दी गई है। अब रहा सहा छत्तीसगढ़ का जो मुख्य भोजन चावल को भी केन्द्र की सरकार ने एपीएल के कोटे को कम कर दिया है। इस सरकार से मेरा निवेदन है कि आम आदमी की सरकार, गरीबों की सरकार कम से कम गरीबों के पेट पर लात न मारे और छत्तीसगढ़, जो कि केवल सात वर्ष की आयु का है, उसके साथ भेदभाव न करे। धन्यवाद।